Issue 10 – October / अक्टूबर - 2023

कृषक सारथी

Monthly Newsletter of
KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LIMITED

For Internal Circulation only

Marketing Director's Message

I am delighted to welcome you to the 10th issue of Krishak Saarathi, a publication that reflects our unwavering commitment to agricultural excellence.

In the spirit of cooperation and growth, I'd like to highlight two remarkable events that have recently shaped our journey. The first, the National Symposium held on the Production of Improved and Traditional Seeds through the Cooperative Sector, hosted by BBSSL brought together some of the brightest minds in the agricultural sphere. It was a platform for sharing knowledge, fostering collaboration, and advancing our collective understanding of seed production and its vital role in modern agriculture.

The second event, the 'National Symposium on Cooperative Exports,' hosted by NCEL in New Delhi, was a testament to our dedication to enhancing the export potential of our cooperative sector. It marked a significant step towards realizing the vision of 'Sahakar Se Samriddhi,' where cooperatives play a pivotal role in rural development and the prosperity of our farmers.

These events are a testament to our commitment to growth, sustainability, and inclusive development. This journey has been supported by the Ministry of Cooperation, which has played a vital role in streamlining regulations and fostering our progress. We look forward to continued collaboration with the Ministry as we work together to create a brighter and more prosperous future for our farmers and rural communities.

V. S. R. Prasad
Marketing Director

EDITOR'S DESK

Dear Readers,

It is with great pleasure that we present the 10th edition of Krishak Saarathi Magazine. As we delve into the pages of this milestone issue, we embark on a journey through the bountiful landscapes of the Rabi season crop. Rabi Season is an important season for the food grains production in our country which is much anticipated for production of Wheat, Mustard, Gram and other important agricultural and horticultural products.

In this edition, we revisit two key events that have left a lasting impact on our cooperative journey. The first event, the National Symposium on Improved and Traditional Seed Production through Cooperatives, brought together agricultural experts to share knowledge and enhance our understanding of seed production, a vital aspect of modern farming.

The second event, the 'National Symposium on Cooperative Exports,' held in New Delhi, showcased our dedication to boosting the export potential of cooperatives, aligning with the 'Sahakar Se Samriddhi' vision for rural development and farmer prosperity.

I would like to extend my heartfelt gratitude to our dedicated team and the entire KRIBHCO family for their unwavering commitment to making Krishak Saarathi a valuable source of knowledge for all our readers. Your continued support and dedication are the driving force behind our success.

Dr. V. K. Tiwari
Dy. GM (Mktg)

Editorial Board

Sh. V S R Prasad, Mktg. Director
Chairman

Dr. V K Tiwari, DGM (Mktg)
Chief Editor

Sh. Sharvan Kumar, CM (Mktg)
Member – FAS

Sh. Devisht Agarwal, DM (MS)
Member – IT and Technical

Sh. Nitesh Kumar Mishra, DM (Mktg)
Editing, Design and Circulation

Sh. Raj Babu Kumar, AM (Mktg)
Member – Agriculture News Updates

Sh. Rishav Arora, AM (MS)
Member – Current Affairs

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिनांक 26.10.2023 को नई दिल्ली में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) द्वारा सहकारी क्षेत्र में उन्नत एवं पारंपरिक बीजोत्पादन' पर राष्ट्रीय संगोष्ठीको संबोधित किया।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिनांक 26.10.2023 को नई दिल्ली में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) द्वारा सहकारी क्षेत्र में उन्नत एवं पारंपरिक बीजोत्पादन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया।

श्री अमित शाह ने BBSSL के Logo, वेबसाइट और Brochure का अनावरण तथा BBSSL के सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर केन्द्रीय सहकारिता राज्यमंत्री श्री बी एल वर्मा, सचिव, सहकारिता मंत्रालय और सचिव, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्देशानुसार 11 जनवरी, 2023 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की स्थापना को मंज़ूरी दी, 25 जनवरी, 2023 को इसका पंजीकरण हुआ, 21 मार्च, 2023 को इसकी अधिसूचना जारी हुई और अब प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी हमने बहुत कम समय में कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये समिति कृषि, बागवानी, डेयरी, मत्स्यपालन सहित हर प्रकार की समितियों की तरह PACS को बीज उत्पादन के साथ जोड़ने का काम करेगी। PACS के माध्यम से हर किसान अपने खेत में बीज उत्पादन कर सकेगा, इसका सर्टिफिकेशन भी होगा और ब्राडिंग के बाद ना सिर्फ पूरे देश बल्कि विश्व में इस बीज को पहुंचाने में ये समिति योगदान देगी। उन्होंने कहा कि इस बीज सहकारी समिति का पूरा मुनाफा सीधे बीज उत्पादन करने वाले किसानों के बैंक खातों में जाएगा और यही सहकारिता का मूल मंत्र है। इस सहकारी समिति के माध्यम से बीजों की उच्च आनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता से बिना कोई समझौता किए इन्हें बरकरार रखा जाएगा और उपभोक्ता के स्वास्थ्य की भी चिंता की जाएगी, इन तीनों बातों का संयोजन करते हुए उत्पादन बढ़ाना ही हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इस सहकारी समिति का लक्ष्य केवल मुनाफा कमाना नहीं है बल्कि इसके माध्यम से हम विश्व की औसत पैदावार के साथ भारत की पैदावार को मैच करना चाहते हैं। इसके साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के अकुशल उत्पादन की जगह किसान को प्रशिक्षण देकर वैज्ञानिक तरीके से बीजों के उत्पादन के साथ हम जोड़ने का काम करेंगे। आज भारत में ही बीजों की आवश्यकता लगभग 465 लाख क्विंटल है, जिसमें से 165 लाख क्विंटल सरकारी व्यवस्था से उत्पादित होता है और कोऑपरेटिव व्यवस्था से ये उत्पादन 1 प्रतिशत से भी नीचे है, हमें इस अनुपात को बदलना होगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि कोऑपरेटिव के माध्यम से बीज उत्पादन के साथ जो किसान जुड़ेंगे, उन्हें बीज का मुनाफा सीधे मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत के घरेलू बीज बाजार का वैश्विक बाज़ार में हिस्सा सिर्फ 4.5 प्रतिशत है, इसे बढ़ाने की ज़रूरत है और इसके लिए बहुत काम करना होगा। श्री शाह ने कहा कि हमें इस भारतीय बीज सहकारी समिति के अगले 5 सालों के लक्ष्य तय करने होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बीज सहकारी समिति की स्थापना केवल मुनाफे और उत्पादन के लक्ष्य तय करने के लिए नहीं हुई है, बल्कि ये R&D का काम भी करेगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा। श्री शाह ने कहा कि बीज नेटवर्क में ICAR, 3 केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, 48 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, 726 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र और केन्द्र और राज्यों की 72 सरकारी एजेंसियां जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमारी किसी से कोई स्पर्धा नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य है कि मुनाफा किसान के पास पहुंचे, प्रमाणित बीजों का उत्पादन बढ़े और इनके निर्यात में भारत का हिस्सा बढ़े। उन्होंने कहा कि इन सभी संस्थाओं को साथ लेकर हम इस बीज कोऑपरेटिव के काम को आगे बढ़ाएंगे और अपने लक्षित सीड रिप्लेसमेंट रेट के प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस संस्था के मूल में इफको, कृभको, नेफेड, एनडीडीबी और एनसीडीसी को जोड़ा गया है जो एक प्रकार से किसान के खेत तक पहुंच रखती हैं।इन संस्थाओं के माध्यम से मल्टीफिकेशन बंद हो जाएगा और सभी सहकारी संस्थाएं एक ही दिशा में एक ही लक्ष्य के साथ एक ही रोड मैप पर काम करेंगी। उन्होंने कहा कि जब सभी संस्थाएं एक रोड मैप पर चलती हैं तो स्वाभाविक रूप से गति बढ़ती है और इनके साथ मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव, राज्यस्तरीय सहकारी संस्थाएं, जिलास्तरीय सहकारी संस्थाएं और PACS भी जुड़ सकेंगे। इस तरह एक ऐसा खाका बनाया गया है जिसमें हर प्रकार की कोऑपरेटिव इसका हिस्सा बन सकती है और उनका सहयोग इस बीज कोऑपरेटिव को मिल सकेगा। श्री शाह ने कहा कि सहकारी नेटवर्क के माध्यम से प्रोडक्शन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, परचेज, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट हम कर सकेंगे क्योंकि अगर बीजों का प्रोडक्शन के बाद टेस्टिंग नहीं होगी, तो गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। इसी प्रकार टेस्टिंग के बाद सर्टिफिकेशन नहीं होता है तो विश्वसनीयता नहीं होगी, सर्टिफिकेशन के बाद प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और लेबलिंग नहीं होगी, तो उसके उचित दाम नहीं मिलेंगे। इसकी उचित वैज्ञानिक तरीके से स्टोरेज से लेकर मार्केटिंग और फिर दुनिया के बाजार में भेजने तक की पूरी व्यवस्था कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से ही की जाएगी। ये पूरी व्यवस्था विश्वस्तरीय और सबसे आधुनिक होगीऔर हमारी कोऑपरेटिव ने करके दिखाया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि उत्पादन, गुणवत्ता, ब्रांडिंग, और मार्केटिंग के क्षेत्र में इन संस्थाओं के सफल अनुभव के माध्यम से बीज उत्पादन, R&D और निर्यात के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ-साथ देश को बीजोत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और बीजों के वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बाने में मदद करेगी और इसका सबसे बड़ा फायदा छोटे किसानों, महिलाओं और युवाओं को होगा। उन्होंने कहा कि देश में क्रॉप पैटर्न चेंज करने के लिए भी अच्छे बीजों का उत्पादन बहुत जरूरी है और जब हम देश के लाखों किसानों को बीज उत्पादन के साथ जोड़ेंगे, तो वह गांव में ऑटोमेटेकली मार्केटिंग मैनेजर का काम करेगा। श्री शाह ने कहा कि यह बीज सहकारी समिति लिमिटेड बहुत सारे उद्देश्यों को सिद्ध करेगी।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह भी है कि पारंपरिक बीजों का संरक्षण किया जाए, क्योंकि हमारे पास बीज की लाखों नस्ल हैं, लेकिन इनके बारे में पूरी जानकारी सरकारी विभागों को भी नहीं है। उन्होंने कहा कि लाखों गांव में हर किसान के पास परंपरागत बीज उपलब्ध हैं, इसका डेटा बनाना, संवर्धित करना और इसका वैज्ञानिक एनालिसिस करके इसके सकारात्मक पहलुओं का एक डेटा बैंक तैयार करना बहुत बड़ा काम है, जिसे भारत सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि हमने इसमें क्लाइमेट चेंज की चिंता को भी सामने रखा है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के इनीशिएटिव से श्री अन्न (मिलेट्स) का जो बड़ा मार्केट आज विश्व में खड़ा हुआ है, इसके बीज भारत के अलावा बहुत कम देशों के पास हैं। रागी, बाजरा, ज्वार और कई अन्य मिलेट्स पर हमारी मोनोपली हो सकती है, अगर हमारी यह बीज कोऑपरेटिव इस पर ध्यान दे।

देश की तीन प्रमुख सहकारी समितियों– इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को–ऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO), **कृषक भारती सहकारी लिमिटेड** (KRIBHCO) **और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ** (NAFED) **तथा भारत सरकार के दो प्रमुख वैधानिक निकाय– राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड** (NDDB) **और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम** (NCDC) **ने संयुक्त रूप से** BBSSL **को प्रमोट किया है।**

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिनांक 23.10.2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) द्वारा आयोजित सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया।

श्री अमित शाह ने NCEL के logo, वेबसाइट और brochure का लोकार्पण तथा NCEL सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्र भी वितरित किए।

इस अवसर पर केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और केन्द्रीय सहकारिता राज्यमंत्री श्री बी एल वर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि आज महानवमी के शुभ दिन राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड का एक प्रकार से औपचारिक उद्घाटन हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा आज़ादी के बाद पहली बार सहकारिता मंत्रालय की स्थापना और उनकी सहकार से समृद्धि की कल्पना को साकार करने की दिशा में हम एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना कई उद्देश्यों के साथ बहुत विचार-विमर्श के बाद की गई। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने कहा कि NCEL की स्थापना के पीछे हमारे लक्ष्यों में निर्यात, विशेषकर कृषि निर्यात, को बढ़ाना, किसानों को समृद्ध बनाना, Crop Pattern Change करना और 2027 तक देश के 2 करोड़ किसानों को उनकी भूमि को प्राकृतिक घोषित करने में सक्षम बनाना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने एक मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी बनाई है जो भारत के प्राकृतिक खेती करने वाले इन 2 करोड़ से अधिक किसानों के ऑर्गेनिक उत्पादों को एक अच्छी पैकेजिंग, विश्वसनीय ब्रांडिंग और उच्च गुणवत्ता के सर्टिफिकेट के साथ वैश्विक बाज़ार में बेचेगी। इससे किसानों को उनके ऑर्गेनिक उत्पादों के अभी मिल रहे मूल्य से लगभग डेढ़ या दो गुना मूल्य सीधे प्राप्त होगा और इससे किसानों के लिए समृद्धि का रास्ता खुलेगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा की गई है। उन्होने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां एकसाथ 4 फसलें हो सकती हैं और अगर इनमें से एक फसल भी बायोफ्यूल के लिए उपयोग हो सके, तो हम भारत की बायोफ्यूल की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद इसे निर्यात भी कर सकते हैं। श्री शाह ने कहा कि NCEL की स्थापना का एक और उद्देश्य है देश में सहकारिता को मज़बूत करना, जिसमें कृषि पर निर्भर आबादी और ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादों का देश की जीडीपी में 15 प्रतिशत योगदान है और इस क्षेत्र से जुड़ी आबादी कुल आबादी की लगभग 60 प्रतिशत है। कोई भी देश अपनी 60 प्रतिशत आबादी को ignore कर अर्थतंत्र को मज़बूत नहीं कर सकता और जिस अर्थतंत्र में देश की 60 प्रतिशत आबादी की जगह ना हो, वो अर्थतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य है कि जीडीपी बढ़ाने के साथ-साथ इन 60 प्रतिशत लोगों को रोजगार देकर उन्हें समृद्ध भी बनाना है और इसका एकमात्र रास्ता है सहकारिता को मजबूत करना। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, देश में सहकारिता के पूरे ढांचे को नई मजबूती देने का भी काम करेगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि निर्यात, किसान की समृद्धि, Crop Pattern बदलने, ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार,

बायोफ्यूल के लिए वैश्विक बाजार में भारत का प्रवेश और सहकारिता को मजबूत करने जैसे 6 उद्देश्यों के साथ सहकारिता क्षेत्र में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की शुरूआत हुई है। इस नई शुरूआत से किसानों और दूध उत्पादों, इसबगोल, जीरा, इथेनॉल और कई प्रकार

के ऑर्गेनिक और अन्य मांग वाले उत्पादों की वैश्विक मांग के बीच एक कड़ी का काम सहकारिता करेगी। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 1500 कोऑपरेटिव्स NCEL के सदस्य बन चुके हैं और ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हर तहसील इसके साथ जुड़ कर किसानों की आवाज़ बने। अब तक NCEL के पास 7,000 करोड़ रूपए के order आ चुके हैं और 15,000 करोड़ रूपए के orders पर negotiation चल रहा है। सहकारिता मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले दिनों में इफको, कृभको और अमूल की तरह राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड भी एक बहुत बड़ा और सफल Cooperative Venture साबित होगा।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि हमारे देश के कुल खाद्य उत्पादन का 30%,चीनी उत्पादन का 30%, दूध उत्पादन का लगभग 17% हिस्सा कोऑपरेटिव्स का है। उन्होंने कहा कि देश के किसानों को होने वाले कुल फाइनेंस का लगभग 42 प्रतिशत कोऑपरेटिव द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि चीनी उत्पादन में सहकारिता का योगदान 30% है लेकिन चीनी के निर्यात में एक प्रतिशत है और दूध उत्पादन में सहकारिता का योगदान 17% है लेकिन दुग्ध उत्पादों के निर्यात में 2% से भी कम है। इसका अर्थ ये है कि सहकारिता क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और उनका दोहन करने के लिए एक जरिया चाहिए था, जो किसान, सहकारी समिति और वैश्विक बाजार के बीच कड़ी बने और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड उस कड़ी के रूप में काम करेगी। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, छोटी समितियां को भी आवश्यक फाइनेंस और उसकी जानकारी उपलब्धता कराएगा, निर्यात की मेंटेलिटी और इसके लिए जरूरी सावधानियों के बारे में जानकारी देगा, निर्यात अनुकूल मैटीरियल के उत्पादन के लिए भी काम करेगा। इसे अलावा NCEL ब्रांड के बारे में सजगता, गुणवत्ता के प्रति जागरूकता, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पाद के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए पैरामीटर तय करने जैसे काम भी नाममात्र शुल्क पर छोटे किसानों के लिए करेगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज किसान के हाथ निर्यात से हुआ मुनाफा नहीं आता है, लेकिन राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के माध्यम से निर्यात का कम से कम 50% मुनाफा किसानों के पास सीधे जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी और फिर 6 माह की बैलेंसशीट बनने के बाद MSP के अनुसार किए गए भुगतान के अतिरिक्त आने वाले मुनाफे का 50 प्रतिशत सीधा किसान के बैंक अकाउंट में जाएगा। इससे निर्यात योग्य उत्पादन बढ़ाने के प्रति किसानों का उत्साह भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड सिर्फ मुनाफे की तरफ ध्यान नहीं देगा, बल्कि किसान पर ध्यान देना इसका मुख्य लक्ष्य होगा। उन्होंने कहा कि निर्यात बढ़ाने के लिए खेत और किसान के स्तर से इसका स्वभाव बनाना होगा, क्रॉप पैटर्न चेंज करना होगा और ब्रांड और पैकेजिंग मार्केटिंग की पूरी व्यवस्था किसान के मन में जागरूकता पैदाकर खड़ी करनी होगी। यह व्यवस्था राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड को खड़ी करनी होगी, तभी हम इन 6 उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकेंगे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि NCEL पूरे सहकारिता क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बनेगी और आने वाले दिनों में इसमें खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, सर्टिफिकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक संपूर्ण निर्यात इकोसिस्टम बनाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाजार संपर्क के लिए Whole of Government Approach के साथ उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और हमारे दूतावासों को जोड़ने का काम भी NCEL करेगा। इसके अलावा बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन हो, इसके लिए FPOs और PACS को साथ रखकर इसका एक डिजाइन तैयार किया जाएगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार निर्यात बढ़ाने के साथ-साथ इसका फायदा किसानों तक पहुंचाने की सुचारु व्यवस्था खड़ी करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियां बनाई हैं- राष्ट्रीय स्तर पर बीज उत्पादन के लिए, ऑर्गेनिक उत्पादों के सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के लिए और तीसरी कोऑपरेटिव निर्यात के लिए बनाई गई है।

नवंबर माह के कृषि कार्य

धान:

धान की शेष पकी फसल की कटाई कर लें.

गेहूँ: गेहूँ की प्रमुख प्रजातियाँ:

HD-2967, HD-3086, HD-3385, PB-550,DBW-332, DBW-327, DBW-302, WH-1224, WH-3086, RJ-4037

(1) सिंचित अवस्था वाली किस्मों के लिए 120 किलो नेत्रजन, 60 किलो फास्फोरस तथा 40 किलो पोटाश प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें। नेत्रजन की आधी तथा फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा बोआई के समय प्रयोग करें । नेत्रजन की शेष आधी मात्रा, दो बार में, पहली एवं दूसरी सिंचाई के बाद डालें।

(2) असिंचित अवस्था में गेहूँ की खेती के लिए 80 किलो नेत्रजन, 40 किलो फास्फोरस तथा 20 किलो पोटाश प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें । बुआई के समय, 40 किलो नेत्रजन तथा फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा डालें नेत्रजन की शेष मात्रा प्रथम एवं द्वितीय सिंचाई पर दें।

चना: चने की प्रमुख प्रजातियाँ:

RVG-202, RVG-204, RVG-205, GNG-2171, Phuley Vikrant, Jaki-9218

(1) यदि चने की बुवाई धान की फसल कटने के बाद करनी हो तो ऐसी स्थिति में बुवाई दिसम्बर के मध्य तक अवश्य कर देनी चाहिए अन्यथा अधिक विलम्ब होने पर पैदावार कम हो जाती है।

(2) खरपतवारो द्वारा फसल में होने वाले नुकसान से बचने के लिए बुवाई से 25-30 दिनों बाद पहली निकाई-गुड़ाई तथा 60-70 दिन बाद दूसरी निकाई-गुड़ाई करनी चाहिए।

राई-सरसों: सरसों की प्रमुख प्रजातियाँ:

RH-725, RH-761

(1) अच्छी पैदावार हेतु बोआई के 25 दिनों के बाद निकौनी कर लेनी चाहिए।

(2) जल-प्रबंधन: दो से तीन सिंचाई इस फसल के लिए काफी है । पहली सिंचाई पौधे की बढ़ोतरी के लिए 25-30 दिनों के अंदर कर देना चाहिए। दूसरी सिंचाई फूल आने पर तथा अंतिम या तीसरी सिंचाई फली बनने के समय करनी चाहिए।

आलू:

(1) अगेता और पिछेता झुलसा रोग से बचाव के लिए इंडोफिल एम 45 या रिडोमिल एम ज़ेड दवा के 0.2% घोल का छिड़काव 2-3 बार करें ।

(2) बीज के लिए लगाये गये आलू के खेत में दोबारा मिट्टी न चढायें तथा लगायी गयी फसल में बार-बार न जायें अन्यथा सम्पर्क से विषाणु रोग फैलने का डर रहता है।

आम:

(1) आम में परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है । अत: फल आने के समय कीटनाशक दवाओं का प्रयोग न करें अन्यथा फलन प्रभावित होती है ।

(2) यदि पत्ती खाने वाले कीड़े का प्रकोप दिखाई दे तो उसके नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफ़ॉस या क्वीनालफास दवा का 1.5 मि.ली. मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 छिड़काव करें ।

लीची:

लीची के पूर्ण विकसित पौधे जिनमें फल लगना प्रारम्भ हो गया हो उसमें फूल आने के 3-4 माह पूर्व पानी नहीं देना चाहिए ।

पपीता:

नमी की कमी अथवा अधिकता के कारण फल उत्पादन कम हो जाता है । इसलिए जाड़े के दिनों में 15 दिन के अंतराल पर तथा गर्मी के दिन में 7-10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। जब पेड़ फल से लदा हो तो उस समय सिंचाई करना अति आवश्यक है ।

आँवला:

फल सड़न: (अल्टरनेरिया अल्टरनेटा) को प्रतिबंधित करने के लिए फल तोड़ने के 15 दिनों पूर्व 0.1 प्रतिशत कार्बेन्डाजिम का छिड़काव करना चाहिए ।

पुष्प व सगंध पौधे:

देशी गुलाब की कलम काटकर अगले वर्ष के स्टाक हेतु क्यारियों में लगा दें.

ग्लेडियोलस में स्थानीय मौसम के अनुसार सप्ताह में एक या दो बार सिंचाई करें.

1,851 agriculture and rural development banks to be computerised

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, OCTOBER 8

Government to computerise 1,851 agricultural & rural development banks

PTI ■ NEW DELHI

The government on Sunday announced it will comput-

In First, Centre To Give Funds To Registrar Of Cooperatives Of All States, UTs

Government to computerise 1,851 ARDBs & state co-op registrars

NEW DELHI: The government on Sunday announced it will computerise state cooperative registrars and 1,851 offices of Agriculture and Rural Development Banks (ARDBs) under a scheme with a budget of Rs 225.09 crore.

Currently, the government is computerising all Primary Agriculture Credit Societies (PACS) in the country.

"On the lines of the computerisation scheme of PACS in the country, a centrally sponsored scheme has been approved for computerisation of 1,851 units of ARDBs of 13 states through a national unified software," the cooperation ministry said in a statement.

State Cooperative Registrars, Agri & Rural Dvpt Banks to be Computerised

New Delhi: The government on Sunday announced it will computerise state cooperative registrars and 1,851 offices of Agriculture and Rural Development Banks (ARDBs) under a scheme with a budget of ₹225.09 crore. Currently, the government is computerising all Primary Agriculture Credit Societies (PACS) in the country.

"On the lines of the computerisation scheme of all PACS in the country, a centrally sponsored scheme has been approved for computerisation of 1,851 units of ARDBs of 13 states through a national unified software," the cooperation ministry said in a statement.

The government has also decided to computerise the offices of Registrar of Cooperatives of all states

total estimated expenditure for this scheme will be Rs 225.09 crore," the statement said.

The implementation of this scheme will not only enable people to quickly access services provided by the cooper-

Centre to give funds to Registrar of Cooperatives of states, UTs for computersation: Amit Shah

BK NEWS SERVICE

New Delhi, Oct 8: In a historic decision and for

Landmark move: Centre to provide funds to State & UT Cooperatives for computerisation

New Delhi, Oct 08: In a historic decision and for the first time, registrar of cooperatives of States and Union Territories (UTs) and Agriculture and Rural Development Banks (ARDBs) are being given funds by the Center

Amit Shah steps in to computerize State, UT Cooperatives

Centre to give funds for digitization

New Delhi, Oct 8: In a historic decision and for the first time, registrar of cooperatives of States and Union Territories (UTs) and Agriculture and Rural Development Banks (ARDBs) are being given funds by the Center for computerisation, Ministry of Cooperation said on Sunday.

The total estimated expenditure for this scheme will be Rs 225.09 crore and it will enable people to quickly access services provided by the cooperative

GoI To Give Funds To Registrar Of Cooperatives Of All States, UTs

New Delhi, Oct 8: In a historic decision and for the first time, registrar of cooperatives of States and Union Territories (UTs) and Agriculture and Rural Development Banks (ARDBs) are being given funds by the Center for computerisation, Ministry of Cooperation said on Sunday.

The total estimated expenditure for this scheme will be Rs 225.09 crore and it will enable people to quickly access services provided by the cooperative departments of the States and the offices of ARDBs as well as bring transparency and uniformity in the functioning of these offices, which will make them more efficient and save the time.

■ More on Page 6

In A First, Centre To Give Funds To Registrar Of Cooperatives Of All States, UTs For Computerisation

कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड

KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LIMITED

कृभको भवन, ए-10, सैक्टर-1, नोएडा - 201301, जिला गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.)
KRIBHCO Bhawan, A-10, Sector-1, NOIDA - 201301, District Gautam Budh Nagar (U.P.)

Designed by Wide Reach Advertising